



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 15 मई, 2018(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-05(05/69)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार 16 मई को नई टिहरी के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार को प्रातः 8:50 पर जीएमवीएन हट्स, टिहरी लेक पहुंच कर टिहरी महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक मंत्रीमण्डल की बैठक(फ्लोटिंग मैरिना बोट) में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट की अहम बैठक को टिहरी झील में आयोजित करने की अभिनव पहल की है। इस तरह की बैठकें राज्य के विकास के लिए बहुआयामी तरीके से फायदेमंद साबित होंगी। इस पहल के पीछे सरकार का स्पष्ट मकसद है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के द्वार जाकर अपने फैसले ले। देहरादून से बाहर राज्य के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना भी इस पहल का हिस्सा है। टिहरी में कैबिनेट बैठक के माध्यम से न सिर्फ टिहरी के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि टिहरी के गौरवशाली इतिहास और उज्ज्वल भविष्य से रूबरू होने का अवसर भी है। कुल मिलाकर टिहरी जैसे दुर्गम जिलों में पलायन और विस्थापन के जो अभिशाप लोगों ने झेले, उनका समाधान तलाशकर उसे टिहरी की ताकत बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बदलाव की किरण को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को ओएनजीसी सभागार से उत्तराखण्ड के प्रथम सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) रूद्रपुर, उधमसिंहनगर का शुभारम्भ किया। यह उत्तराखण्ड का पहला तथा देश का आठवाँ सीजीडी है। 500 किलोमीटर की यह पाइप लाइन 2020 तक पूरी हो जाएगी। इसके द्वारा 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा इस पाइप लाइन के अर्न्तगत जसपुर में एक, काशीपुर में दो, बाजपुर में एक, रूद्रपुर में तीन, किच्छा में एक, खटीमा में एक तथा कुल मिलाकर 10 स्थानों को सीएनजी स्टेशन के लिए चिह्नित किया गया है। लगभग 250 करोड़ रुपये की इस परियोजना से उत्तराखण्ड में काशीपुर से रूद्रपुर/पन्तनगर तक क्षेत्र आच्छादित करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्युलेट्री बोर्ड द्वारा आयोजित 9वें सीजीडी बिल्डिंग राउन्ड रोड शो में प्रतिभाग किया।

पिरूल बनेगा कमाई का जरिया –मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूद्रपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्युलेट्री बोर्ड तथा अदानी ग्रुप के संयुक्त प्रयासों से आज रूद्रपुर में घरेलू गैस की आपूर्ति गैस पाइप लाइन द्वारा आरम्भ हो गई है। राज्य सरकार के छः माह पूरे होने पर हमने वादा किया था कि दून वैली को भी सीएनजी, पीएनजी पर निर्भर बनाएंगे। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं, आशा है कि 2019 तक देहरादून में भी सीएनजी, पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून एवं दून वैली पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील है। उत्तराखण्ड पुरे देश को प्राणवायु देता है। यह महत्वपूर्ण पहल है। हिमालय तथा उत्तराखण्ड के जंगल, नदियाँ तथा पर्यावरण देश के लिए वरदान है। राज्य सरकार द्वारा पिरूल से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जंगलों में लगभग लाख मीट्रिक टन है। पिरूल को आय का जरिया बनाया जाएगा, तारपीन बायोफयूल आदि का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना से 60000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 150 मेगावॉट बिजली पैदा होगी। बायोफयूल उत्पादन के लिए देहरादून के भूमि आवंटित की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लगाया जा सके।

रोजगार का मतलब स्वरोजगार है ना कि सरकारी नौकरी—मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र

स्वरोजगार से ही पलायन पर रोक—मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निवेशकों से अपील की किसी भी परियोजना या योजना पर काम करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पलायन राज्य की गम्भीर समस्या है। शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं के निर्माण समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। रोजगार का मतलब स्वरोजगार है ना कि सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वरोजगार से ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लग सकता है।

पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्युलेट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी के श्राफ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीजीडी के लिए अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर इस पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। गेल द्वारा 2019 तक हरिद्वार में गैस पाइप लाइन पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के अनुमोदन शीघ्र प्राप्त हो रहे हैं। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र, ऋषिकेश के औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आरम्भ किया जाएगा।

कार्यक्रम को पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्युलेट्री बोर्ड के सदस्य श्री एस पी गर्ग, अतिरिक्त सलाहकार पीएनजीआरबी श्री अरविन्द कुमार आदि ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर पीएनजीआरबी की अधिकारी, अदानी ग्रुप के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में निवेशक भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा। मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली, पानी, सड़क, इन्टरनेट सहित तमाम जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों का आह्वान किया कि उन्हें 2020 के लक्ष्य को 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवाँ वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है। जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है। सरकार के लिए कर्मचारी हित सर्वोपरि है। साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विन्दुवार चर्चा की। जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव वित्त श्री अरुणेंद्र सिंह चौहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री श्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना एवं विभागीय कार्यों की बैठक बुलाई थी। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित न होने एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण न दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बैठक हेतु नई तिथि निर्धारित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय बिश्नोई की पहल की सराहना की है। श्री बिश्नोई ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुरक्षा में कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनका आवास कार्यस्थल से पांच या सात कि०मी० की दूरी पर स्थित है आवगमन के लिए साईकिल के प्रयोग करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून शहर में प्रदूषण को कम करने हेतु हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस पहल में सहयोग की अपील करने को कह है। इस पहल से समाज में अच्छा संदेश जायेगा एवं शहर में प्रदूषण एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु उनका सहयोग भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के निराकरण में अपना सहयोग देना है तभी इस समस्या से निजात मिल पायेगी।